भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2070
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजमुंदरी में जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाएं

†2070. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राजमुंदरी में ऐसे कुल कितने घर हैं जिन्हें वर्तमान में 24x7 निर्बाध पाइप जलापूर्ति की जाती है और शहर की कितनी प्रतिशत आबादी अभी भी अनियमित या टैंकर-आधारित जल सेवाओं पर निर्भर है;
(ख) राजमुंदरी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और साथ ही शहर तथा उपनगरीय क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों की स्थापना के संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;
(ग) सरकार जेजेएम परियोजनाओं में, विशेषकर राजमुंदरी जैसे अत्यधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में निधि उपयोग, रिसाव का पता लगाने और जल संरक्षण उपायों के संदर्भ में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है; और
(घ) जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति अवसंरचना, विलवणीकरण संयंत्रों और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पूर्वी गोदावरी जिले के राजमुंदरी ग्रामीण क्षेत्र में, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 18,372 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। 29.07.2025 तक, कुल 31,485 ग्रामीण परिवारों में से राजमुंदरी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 11,030 और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है।

शहरी क्षेत्र के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 शहरों (विलय किए गए 15 शहरों सहित 485 शहरों) के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। मिशन के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफानी जल की निकासी, हरित स्थान तथा पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0 योजना 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाया गया है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जल निकायों का पुनरुद्धार, हरित स्थानों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत के अंतर्गत राजमुंदरी, आन्ध्र प्रदेश में 97.09 करोड़ रुपए की कुल 07 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 55.75 करोड़ रुपए के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन परियोजनाओं में 2.37 करोड़ रुपये की 01 जल आपूर्ति परियोजना, 12.09 करोड़ रुपये की 01 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना, 1.96 करोड़ रुपये की 03 पार्क और हरित स्थान परियोजनाएं तथा 80.67 करोड़ रुपये की 02 जल निकासी परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 230.34 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 100.24 करोड़ रुपये की 02 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 110.23 करोड़ रुपये की 03 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं तथा 19.87 करोड़ रुपये की लागत वाली 05 जल निकाय नवीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में 02 जलापूर्ति परियोजनाओं में से अमृत 2.0 के तहत 95.14 करोड़ रुपये की कुल 01, 24x7 जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी दी गई है।